www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 22 | गोरखपुर, 08 दिसम्बर 2024 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

हमारी संस्कृति में सेवा सबसे बड़ा धर्म, अस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान: पीएम मोदी

गुजरात (अहमदाबाद)। अहमदाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सुवर्ण महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भगवान स्वामी नारायण को नमन करता हूं- आज 103वीं जयंती है। उन्होंने आगे कहा कि जब यूक्रेन में युद्ध बढ़ने लगा तो भारत सरकार ने तुरंत वहां फंसे भारतीयों को निकालने का फैसला किया। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय पोलैंड पहुंचने लगे। लेकिन चुनौती थी कि उस युद्ध के माहौल में पोलैंड पहुंचे भारतीयों को कैसे अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जाए।

मोदी ने आगे कहा कि उस समय मेरी बीएपीएस के एक संत से बात हुई और मुझे लगता है रात के 12 या 1 बजे होंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि बड़ी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे भारतीयों की मदद के लिए मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है और मैंने देखा कि कैसे आपका संगठन रातोंरात पूरे यूरोप से बीएपीएस कार्यकताओं को एक साथ लाया। इअढर की ये ताकत, वैश्विक स्तर पर मानवता के हित में आपका योगदान बहुत सराहनीय है और इसलिए आज कार्यकर्ता सुवर्ण महोत्सव पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों पूरी दुनिया में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की चर्चा हो रही है। इस दिशा में आपके प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप भारत के विकास को गति देने वाले कई काम कर सकते हैं, जैसे फिट इंडिया। उन्होंने कहा कि युवा विचारों को नए अवसर देने के लिए जनवरी में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने विचार देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा परमो धर्मः - ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। सेवा को श्रद्धा, आस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान दिया गया है।

मोदी ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना की गई है। मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस घटना और उस मंदिर की पूरी दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को दुनिया ने देखा है। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता देखी है। ऐसे प्रयास दुनिया को भारत के सांस्कृतिक गौरव और मानवीय उदारता से परिचित कराते हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

हमारा राष्ट्र और धर्म सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे: योगी आदित्यनाथ

वाराणसी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिसम्बर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर आक्रामक लहजा अपनाते हुए कहा जब तक हमारे धर्म सुरक्षित है, तभी तक हम भी सुरक्षित हैं। योगी यहां स्वर्वेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग संत-समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव में शामिल होने के लिये आये थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ सदगुरु सदाफल महाराज ने आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। योगी ने कहा, 'अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक कार्य पूरा हुआ तो अगले कार्य की शुरूआत कर देनी है, लेकिन हर कार्य देश के नाम, सनातन धर्म के नाम पर होना चाहिए।

एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है।

इसी के साथ 13 जनवरी से प्रयागराज में प्रारम्भ होने जा रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक कुंभ यहां पर है, तो दूसरा महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिला दी है। यही नहीं यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं।

पीएम मोदी के कार्यकाल में वाराणसी में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप देख रहे होंगे कि आज काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में काशी को चमका दिया है। आज काशी में नमो घाट है। देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घाट है, जहां हेलीपैड भी है। काशी में देव मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य- चाहे सड़क, रेल और वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, जो 2014 से पहले था उससे 100 गुना बेहतर अब है। अब काशी से हल्दिया के बीच जलमार्ग का उपयोग करते हुए भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं।

मायावती ने बांग्लादेश में दलितों के साथ हो रही हिंसा पर सपा-कांग्रेस की चुप्पी पर कसा तंज

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू अत्याचार का शिकार हो रहा है। इनमें ज्यादातर लोग दलित और कमजोर वर्ग के हैं। इसीलिये कांग्रेस पार्टी इस मामले पर चुप है और यही कारण है कि वह संभल-संभल चिल्ला रही है। मायावती ने कहा कि इस मामले में सपा हो या कांग्रेस सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, जिससे दलित समाज के लोगों पर अत्याचार कम हो सके।

बता दें बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार को जबरन हटाया गया है तब से वहां अल्पसंख्यक यानी हिन्दू समुदाय के हालात खराब बने हुए हैं। यहां आए दिन उन पर हमले किए जा रहे है। ये हमले इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से ही हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चन्द्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी सहित तमाम ऐसे दल जो मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत करते हैं चुप्पी साधे हुए हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष देश व जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के मुद्दे उठा रहा है। खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब तक इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोला है। ये केवल अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करने में लगी हुई हैं। इन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, ये पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़वा रही हैं.। मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा। मायावती ने चंद्रशेखर आज पर तंज कसते हुए कहा कि इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि जिनके वजह से दलित वर्ग के सांसद संसद में पहुंचे हैं, वो भी अपने पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप बैठे हैं।

गौरतलब हो, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित है। वहां हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार दलित वर्ग हो रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को बढ़-चढ़ कर निभाए। वहां की सरकार से बातचीत कर शोषण से शिकार लोगों को भारत वापस लाया जाए।

मांग केंद्र सरकार से संबंधित, राज्य से नहीं : बलजीत कौर

हरियाणा । पंजाब की सामाजिक न्याय मंत्री बलजीत कौर ने शनिवार को किसानों के चल रहे ' दिल्ली चलो' विरोध मार्च के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि किसानों की मांग सीधे केंद्र में है, राज्य में नहीं। एएनआई से बात करते हुए कौर ने कहा, 'किसानों की सभी मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं, राज्य सरकार से नहीं।' पंजाब के किसानों ने मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन की एक नई लहर शुरू कर दी है।

बलजीत कौर ने अपने किसानों के समर्थन के लिए पंजाब के प्रयासों पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार से उनकी शिकायतों का समाधान करने का आह्वान किया। कौर ने कहा कि पंजाब एक कृषि समृद्ध राज्य है और केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। पंजाब ने किसानों को मदद प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले दिन में, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि किसानों को अपनी जरूरतों को रखने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहिए। खंडेलवाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। समय-समय पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। अगर अब भी कुछ बाकी है तो किसानों को कृषि मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपनी जरूरतें रखनी चाहिए। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार को कहा कि उन्हें अपने मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत के लिए केंद्र से कोई संदेश नहीं मिला है और कहा कि 101 किसानों का एक समूह 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा।

शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना मार्च स्थगित कर दिया। पंजाब-हरियाणा सीमा पर उन्हें रोकने वाले सुरक्षाकर्मियों द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले के कारण उनमें से कुछ के घायल होने के बाद उन्होंने दिन भर राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च किया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं।

महिलाओं पर बढ़ता बोझ: परिवार नियोजन में पुरुषों की कम भागीदारी

कई पुरुष इसे अपनी 'मर्दानगी' पर आघात मानते हैं। वहीं, पारंपरिक धारणाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ने भी इस प्रक्रिया को अपनाने में रुकावटें खड़ी की हैं। पुरुष नसबंदी महिलाओं की तुलना में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अपनाने से न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम होंगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह शिक्षा, जागरूकता, और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से परिवार नियोजन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करे। परिवार केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। पुरुषों की भागीदारी से परिवार नियोजन अधिक सफल और संतुलित हो सकता है।

भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य नसबंदी जैसे तरीकों के जरिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। वर्षों के साथ, इस पहल ने जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व की दिशा में प्रगति की। हालांकि, गर्भनिरोधक उपायों में पुरुष नसबंदी जैसे सरल और सुरक्षित विकल्प मौजूद होने के बावजूद, यह आज भी सामाजिक स्तर पर व्यापक स्वीकृति हासिल नहीं कर पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं का केवल 0.3% हिस्सा है। नीतिगत प्रयासों के बावजूद, नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है, जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाओं को ज्यादा ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। 1952 से अग्रणी परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बावजूद, भारत में नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है। नसबंदी दरों में लैंगिक असमानता और गर्भनिरोधक में पुरुषों की कम भागीदारी के पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड हैं। भारत में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर परिवार नियोजन को मुख्य रूप से महिला की ज़िम्मेदारी मानती हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि नसबंदी के लिए मुख्य रूप से महिलाएँ ज़िम्मेदार हैं, जबकि पुरुष पुरुषत्व और अहंकार की चिंताओं के कारण इसका विरोध करते हैं, जिससे नसबंदी कम स्वीकार्य हो जाती है।

बहुत से पुरुष-पुरुष नसबंदी के लिए उपलब्ध विकल्पों जैसे कि पुरुष नसबंदी के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और स्वास्थ्य कार्यकताओं दोनों में अक्सर नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जो कि कम आक्रामक और सुरक्षित विकल्प है, जिसके कारण कम पुरुष इस प्रक्रिया को चुनते हैं। वेतन हानि का डर और दैनिक आय पर नसबंदी के प्रभाव के कारण पुरुष इस प्रक्रिया को चुनने से हतोत्साहित होते हैं। वेतन हानि की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद प्रोत्साहन का उपयोग सूचना के खराब प्रसार के कारण कम किया जाता है, जिससे कई पुरुष उपलब्ध वित्तीय सहायता से अनभिज्ञ रह जाते हैं। व्यापक धारणा है कि पुरुष नसबंदी वास्तव में जितनी जोखिम भरी है, उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरी है, जिसके कारण पुरुष इस प्रक्रिया को अपनाने से कतराते हैं। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी, जिसमें साइड इफेक्ट और जटिलताओं का डर शामिल है, अक्सर पुरुषों को इस प्रक्रिया पर विचार करने से रोकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी है, जिससे पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत के नसबंदी कार्यक्रम में चुनौतियाँ सूचित सहमति का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं पर नसबंदी प्रक्रियाओं के निहितार्थों को पूरी तरह समझे बिना दबाव डाला जाता है या उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है। 2014 में छत्तीसगढ़ में हुए कुख्यात नसबंदी कांड में, जहाँ एक असफल नसबंदी शिविर के बाद 15 महिलाओं की मौत हो गई थी, सूचित सहमति के प्रति उपेक्षा को उजागर किया। नसबंदी प्रक्रियाएँ अक्सर अपर्याप्त नसबंदी प्रथाओं के साथ खराब सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाओं में की जाती हैं, जिससे संक्रमण और जटिलताएँ होती हैं। नसबंदी के लिए सरकारी लक्ष्य अक्सर स्वास्थ्य कार्यकताओं पर कोटा पूरा करने का दबाव डालते हैं, जिससे देखभाल की गुणवत्ता और नैतिक विचारों से समझौता होता है। नसबंदी महिलाओं के लिए असंगत रूप से लक्षित है, जो लैंगिक असमानता को कायम रखती है और प्रजनन विकल्पों को सीमित करती है। ठ्ठक्कर-4 (2015-16) के अनुसार, महिला नसबंदी 37.9% है, जबकि पुरुष नसबंदी केवल 0.3% है, जो भारत में नसबंदी जिम्मेदारियों के विषम वितरण को उजागर करता है। नसबंदी करवाने वाली महिलाओं को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके आत्मसम्मान और कल्याण को प्रभावित करता है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने पुरुष नसबंदी के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कार्यान्वयन धीमा है।

नीतिगत पहलों के बावजूद, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में पुरुषों की भागीदारी को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण पुरुष नसबंदी की दरें स्थिर हो गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रित शैक्षिक अभियान अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सूचना अभियानों को नो-स्केलपेल नसबंदी के लाभों पर जोर देना चाहिए, इसकी सुरक्षा और न्यूनतम रिकवरी समय पर प्रकाश डालना चाहिए। पुरुषों को नसबंदी का विकल्प चुनने के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन देना भागीदारी बढ़ा सकता है। नसबंदी सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना आवश्यक है। पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं में अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना पुरुषों के लिए सेवाओं तक पहुँच को आसान बना देगा। परिवार नियोजन पहलों को सीधे पुरुषों को लक्षित करना चाहिए, पुरुष नसबंदी और अन्य पुरुष गर्भनिरोधक विधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिक पुरुषों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषत्व और परिवार नियोजन के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण को चुनौती देने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक अभियानों को सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए काम करना चाहिए, यह दिखाते हुए कि पुरुष नसबंदी पुरुषों के लिए एक ज़िम्मेदार और सशक्त विकल्प है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 तक 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करना परिवार नियोजन में लैंगिक समानता के लिए महत्त्वपूर्ण है। सांस्कृतिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं को सम्बोधित करने से पुरुष भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाएँ, जैसे सामुदायिक नेता भागीदारी और लक्षित शिक्षा, प्रगति को गति देंगी। पुरुष नसबंदी महिलाओं की तुलना में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अपनाने से न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम होंगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह शिक्षा, जागरूकता, और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से परिवार नियोजन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करे। परिवार केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। पुरुषों की भागीदारी से परिवार नियोजन अधिक सफल और संतुलित हो सकता है।

-प्रियंका सौरभ

बांग्लादेश की धरती पर भारत के खिलाफ साजिशें

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की संसद तक में यह मुद्दा उठ चुका है। अब अमेरिका में भी इसके खिलाफ राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के करीब बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। इसके बावजूद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों से लेकर चीन-पाकिस्तान तक के दबाव में अपना भारत विरोधी एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यूनुस सरकार ने एक और ऐसा कदम उठाया है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ किए गए मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े एक समझौते को रद्द कर दिया है। इस समझौते से भारत अपने नॉर्थईस्ट राज्यों में इंटरनेट की स्पीड और कवरज बढ़ाने की जुगत भिड़ा रहा था, लेकिन अब यह उम्मीद टूट गई है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हमलों के बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों में से भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करने में जुटी हुई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की एथेनिक क्लींजिंग चल रही है। 53 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भेज रहा है। खालिदा ज़िया और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकातें भी हो रही हैं। बांग्लादेश में वही हो रहा है जो पहले बाबर ने किया फिर कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए भारत को टारगेट कर रहा है। वह भी 3 तरफ से। पाकिस्तान का पहला शिकार बांग्लादेशी हिंदू, जिनपर इतने अत्याचार हो रहे है कि हर परिभाषा छोटी पड़ जाए. दूसरा हिस्सा है बांग्लादेशी फौज को मदद, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना चाहता है और तीसरा भारतीय सामानों का बहिष्कार...ताकि भारत को आर्थिक चोट पहुँचे। बांग्लादेश ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और त्रिपुरा (अगरतला) में अपने शीर्ष राजनयिकों को 'परामर्श' के लिए वापस बुलाया है। वहीं बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नोटों से भी हटा दी गई है।

भारत के नॉर्थ-ईस्ट इलाके के कई राज्यों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण भारत ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश का उपयोग रीजनल डिजिटल हब के तौर पर किया जाना था, जिसमें बांग्लादेशी सीमा पर इंटरनेट सर्किट स्थापित कर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 'बैंडविड्थ ट्रांजिट' सुविधा देनी थी। यह काम भारती एयरटेल को बांग्लादेशी कंपनियाँ समीट कम्युनिकेशंस और फाइबर एट होम के साथ मिलकर करना था। यह प्रस्ताव इन कंपनियों ने बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के सामने पेश किया गया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी।

यूनुस सरकार ने अब इस समझौते की सैद्धांतिक मंजूरी खत्म कर दी है। इसे रद्द करने का आदेश जारी करते हुए इससे बांग्लादेश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने का तर्क दिया है। हालांकि यह फैसला केवल भारत विरोधी नहीं है। दरअसल इस ट्रांजिट लिंक को तैयार करने के लिए एयरटेल के साथ जुड़ी कंपनी समीट कम्युनिकेशंस के चेयरमैन मोहम्मद फारिद खान का शेख हसीना की अवामी लीग से भी नाता है। वे अवामी लीग के सांसद फरीक खान के छोटे भाई हैं। यह भी यूनुस सरकार के फैसले का कारण माना जा रहा है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने बताया कि ढाका के नमहट्टा स्थित इस्कॉन मंदिर में चरमपंथियों की भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि नमहट्टा के मंदिर में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात चरमपंथी मुस्लिमों ने हमला करने के बाद सारी मूर्तियों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी है। पूरा मंदिर जला दिया गया है। ये मंदिर ढाका जिले के तुराग पुलिस थाने के अंतर्गत धौर गाँव में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस्कॉन इन घटनाओं की जानकारी लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को दे रहा है, लेकिन पुलिस-प्रशासन इन्हें नहीं रोक रहा है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अमेरिका में भी चिंता जताई गई है। भारतीय मूल के अमेरिकियों ने इसके खिलाफ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब और शिकागो में अगले दो दिन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। यह प्रोटेस्ट मार्च हिंदू एक्शन संगठन की तरफ से व्हाइट हाउस के पास 'बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार' नाम से सोमवार को आयोजित होगा, जबकि रविवार को शिकागो में 'नरसंहार रोकें: बांग्लादेश में हिंदुओं की जान बचाएं' के नाम से किया जाएगा। इनमें अमेरिका के नामी-गिरामी भारतीय लीडर मौजूद रहेंगे।

बांग्लादेश की धरती पर कट्टरपंथियों के दबाव में फंसी मुहम्मद यूनुस सरकार ने अब पाकिस्तान को खुलकर मनमानी करने की छूट दे दी है। इससे वहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में पाकिस्तान रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी बना रहा है। इन रोहिंग्या आर्तकियों को भारत में हमले करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज से 53 साल पहले लाखों बांग्लादेशियों ने...पाकिस्तान के क्रूर शासन से आजादी के लिए कुबार्नी दी थी। लेकिन वह कुर्बानियाँ अब कब्र में दफ्न कर दी गई हैं...और बांग्लादेशी कट्टरपंथी पाकिस्तान को अपना रहनुमा मानने लगे हैं।

बांग्लादेशी चिल्ला-चिल्ला कर पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा इतिहास पढ़ा होता तो अफगानिस्तान नजर आता, जहाँ पाकिस्तान ने दखल दी। तालिबान खड़ा किया और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अगर बांग्लादेश अब भी इस साज़िश को नहीं समझ पाया...तो शायद बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान कहा जाएगा।

-प्रियंका सौरभ

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत विरोधी लहर चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी चरम पर है। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप खड़े किए गए हैं। ये सभी कैंप्स उन इलाकों में हैं, जहाँ से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहे हैं। भारतीय बॉर्डर के नजदीक ही इन आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंपा गया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर वापस भेज दिया गया। असम पुलिस के कर्मियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास छह बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों की पहचान मोहम्मद दीदारुल इस्लाम, संतू खान, इस्माइल हुसैन राहत, साकिब हुसैन, शाति अख्तर और मीम शेख के रूप में हुई। शर्मा ने कहा, उन सभी को वापस (बांग्लादेश) भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हालांकि, यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को भारत-बांग्लादेश सीमा के किस सेक्टर से पकड़ा गया था। इस वर्ष अगस्त में बांग्लादेश में अशांति फैलने के बाद से अब तक लगभग 167 लोगों को घुसपैठ करने के लिए पकड़ा गया और वापस भेज दिया गया। बांग्लादेश में अशांति फैलने के बाद से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उत्तर-पूर्व में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।

दूषित जल पीने से दो लोगों की मौत, 19 भर्ती

चेन्नई। शहर में कथित तौर पर दूषित पेयजल के कारण बृहस्पतिवार को दो व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 19 अन्य का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों हालचाल पूछा।

उन्होंने बताया कि पानी के नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए गिण्डी स्थित किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च भेजा गया है। मंत्री सुब्रमण्यम ने संवाददाताओं को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा।

मृतकों की पहचान 56 वर्षीय तिरुवेथी और 42 वर्षीय मोहनरांगम के रूप में हुई है। अस्पताल के अनुसार मोहनरंगम को मृत अवस्था में लाया गया था। पल्लावरम के निवासियों ने दावा किया कि शहर में हाल ही में हुई बारिश के दौरान उनके क्षेत्र में पीने का पानी सीवेज के पानी में मिल जाने के कारण दूषित हो गया। सुब्रमण्यन ने बताया कि कुल 34 व्यक्तियों को भर्ती कराया गया जिनमें से 14 को छुट्टी दे दी गई तथा 19 का वर्तमान में उपचार किया जा रहा है।

वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे : अमित शाह

जोधपुर। सीमा सुरक्षा बल का 59 वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। बीएसएफ के स्थापना दिवस की गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत-बहुत बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि बीएसएफ के साथ में स्थापना दिन के लिए यहां पर परेड करने का जो निर्णय किया। इसका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं. पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावा कोई उच्च स्थान नहीं है। जो वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे। शौर्य बलिदान इसके बल पर ही अपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का गौरव हासिल किया। आप सीमा पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत किया. सीमा पार से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना आती है। तब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है आपने उसे बहुत बखूबी निभाया। इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल्कि सबसे छोटा जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र है। मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत-बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूं। यहां आने से पहले मैं 1992 शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको भी मैं सेल्यूट करके यहां आया। मैं आज 1992 जवानों के परिवारजनों को बताना चाहता हूं। आपने निश्चित रूप से आपके परिवारजनों को खोया है। आपके परिवारजन की बहादुरी, समर्पण और वीरता अतुलनीय है. आपके कारण इरक्रने देश की सुरक्षा के इतिहास में कई स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना गौरवपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सफलता की। युगों युगों तक देश की जनता आपके परिवारजनों की ऋणी रहेगी।

▶ पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाई सजा

दुष्कर्म एवं हत्यारोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

अजमेर। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रहने की सजा सुनाई है।

मामला अजमेर जिले के ग्रामीण इलाके पीसांगन का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक अरशद ने अपने आप को हिंदू बताकर नाबालिक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार किया।

पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। शनिवार को अजमेर की पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के लोग अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी अरशद ने अपने आपको हिंदू बताकर पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया।

पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने छोटे चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इस पर न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 30 गवाह और 88 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

अभियोजन पक्ष में इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाने के लिए अपील की थी। विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला पीसांगन का है, जहां पर पीड़िता के परिवार की ओर से धारा 376, 302, 364 व पॉक्सो 3 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस पर आज न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।

निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में सफाई का बिल्कुल अभाव

जयपुर। हवामहल विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर में जनसुनवाई के दौरान विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य को व्यास कॉलोनी के रहवासियों द्वारा कॉलोनी के घर में चल रही अवैध बेकरी व ब्रेड की फैक्ट्री चलाए जाने की शिकायत पर विधायक ने खुद जाकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में सफाई का बिल्कुल अभाव और भारी गंदगी पाई गई। फैक्ट्री में नकली घी का उपयोग कर खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। इसके साथ ही खुले में और टॉयलेट के पास खाद्य पदार्थ रखे गए थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।

विधायक ने मौके पर पाई गई गंभीर शिकायतों पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को फूड सेफ्टी नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी अनियमित गतिविधियां जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हैं और बीमारियों का कारण बनती हैं। इस तरह के अवैध और अस्वच्छ कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जनता की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

▶ हिंदुत्व एजेंडे को धार देने में जुटे भजनलाल,

आक्रामक तरीके से बढ़ाया जा रहा हिन्दुत्व का एजेंडा

जयपुर। उत्तरप्रदेश के बाद राजस्थान में भी संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक बीजेपी ने लव जिहाद के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से प्रचारित किया था, पिछले दिनों मथुरा में संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में ह्यलव जिहादह्ल के खिलाफ प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल- 2024 लाने जा रही है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। यह केवल शुरूआत है। कैबिनेट के ऐलान के बाद रविवार को राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रेस कांफ्रेंस करके लव जिहाद पर कानून लाए जाने को ऐतिहासिक फैसला बता दिया। यह सामान्य घटना नहीं है क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और हो सकता है कि यह कांफ्रेंस संघ के एजेंडे के तहत ही की गई हो। हालांकि राजस्थान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार भी 2 बार 2006 व 2008 में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाई थी लेकिन राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं मिली थी। पिछले 16 साल यह विधेयक राष्ट्रपति भवन में अटका रहा और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यह बिल कानून का रूप नहीं ले पाया। इसके बाद भजनलाल सरकार ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया है। राजस्थान से पहले कई राज्यों में धर्म के गैरकानूनी रूपांतरण को लेकर कानून बनाए जा चुके हैं। इनमें 27 नवंबर 2020 को उत्तरप्रदेश की योगी सरकार धर्म के गैरकानूनी परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लाई थी, इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में मध्यप्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 लागू किया। हरियाणा में तत्कालीन मनोहरलाल खट्टर सरकार ने भी हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम, 2022 बनाया।

देश में अब तक जिन राज्यों में भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पारित हुए हैं, उनमें कानून धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और सभी धार्मिक वर्गों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। आज तक धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं बना है। इसके अलावा 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी क्षमता नहीं है। हालांकि संसद में कई बार धर्म परिवर्तन को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए लेकिन कभी पास नहीं हो पाए। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन से किए गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए 'धर्म की स्वतंत्रता' कानून बनाए हैं। इनमें ओडिशा (1967), मध्यप्रदेश (1968), अरुणाचल प्रदेश (1978), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), गुजरात (2003), हिमाचल प्रदेश (2006 और 2019), झारखंड (2017) और उत्तराखंड (2018), हरियाणा (2022), मध्यप्रदेश (2020), उत्तरप्रदेश (2024) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश (2019) और उत्तराखंड के कानून भी ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करते हैं, यदि यह केवल गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु (2002) और राजस्थान (2006 और 2008) राज्यों ने भी इसी तरह के कानून पारित किए थे। हालांकि तमिलनाडु के कानून को 2006 में (ईसाई अल्पसंख्यकों के विरोध के बाद) निरस्त कर दिया गया था, जबकि राजस्थान के मामले में बिलों को क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली थी। एनडीए सरकार की अगुवाई में 2029 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान लव जिहाद का मुद्दा जमकर उछाला गया। इसके बाद उत्तरप्रदेश के विधि आयोग ने जबरन/ धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए नवंबर 2019 में धर्म परिवर्तन को विनियमित करने के लिए एक नया कानून बनाने की सिफारिश की। इस सफिरिश पर अमल करते हुए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने 2020 में में अध्यादेश जारी कर दिया। यूपी के बाद एमपी सरकार ने भी धार्मिक धर्म परिवर्तन को विनियमित करने के लिए जनवरी 2021 में एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया। इसके बाद जुलाई 2024 में यूपी विधानसभा ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले कलेक्टर को पूर्व में सूचना देनी अनिवार्य है। इसमें यूपी में धर्मांतरण करने वालों को एक महीने पहले सूचना देनी होती है, जबकि एमपी में पुजारी या आयोजकों को भी 60 दिन पहले सूचना देनी होती है। यूपी में धर्मांतरण का आवेदन मिलने के बाद डीएम प्रस्तावक की पुलिस जांच करवाता है कि धर्मांतरण जबरन या लालच में तो नहीं करवाया जा रहा।

एमपी अध्यादेश में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण हुए अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसी भी अदालत के लिए डीएम की मंजूरी को एक पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य बनाता है। यूपी अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के बाद की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। धर्म परिवर्तन के बाद धर्म परिवर्तन की तिथि से 60 दिनों के भीतर धर्मांतरित व्यक्ति को डीएम को विभिन्न व्यक्तिगत विवरणों के साथ एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। डीएम घोषणा की एक प्रति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा और धर्म परिवर्तन पर किसी भी आपत्ति को दर्ज करेगा।

घूँघट की बगावत

8 दिसम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित राजनीतिक हस्तियों ने दी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि

भुवनेश्वर। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के एजी स्क्वायर पर जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वह हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गईं। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज का दौरा करने का भी कार्यक्रम बनाया है।

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर किए अपने पोस्ट में कहा, डॉ. बी.आर आंबेडकर को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर - हमारे संविधान के निमार्ता, एक राजनेता और दूरदर्शी हैं, जिन्होंने सामाजिक असमानताओं के खिलाफ अथक संघर्ष किया। न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के प्रति उनकी गहन प्रतिबद्धता सभी को प्रेरित करती रहती है। आइए हम उनके आदर्शों को बनाए रखने और अधिक समावेशी भारत की दिशा में लगातार काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ह्लराष्ट्रनिमार्ता, सामाजिक न्याय के प्रहरी और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समतामूलक समाज का उनका स्वप्न, उनकी अमूल्य शिक्षाएं और संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। काग्रेस पार्टी ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। उन्होंने पार्टी की तरफ से अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ह्लभारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कोटिः नमन। उनके आदर्श और विचार युगों-युगों तक हमें न्याय की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, ह्लमहापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए, उनके विचार और दृष्टिकोण भारत को प्रेरित करते रहते हैं। राष्ट्र उनके अपार योगदान के लिए उनका ऋणी रहेगा। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि।

जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें : मंडलायुक्त

गोरखपुर । मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से ही सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है और जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एंव समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथकिता है। अतः मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मण्डलायुक्त ने सदर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहने पर क्षेत्राधिकारी गण कैन्ट, गोरखनाथ, चौरीचौरा कैम्पियरगंज, नायब तहसीलदार पिपराइच, थानाध्यक्ष गण राजघाट, तिवारीपुर, कोतवाली, शाहपुर, चिलुआताल, बेलीपार, झंगहा, पीपीगंज महिला थानाध्यक्ष, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र चरगांवा, प्रा0 स्वा0 केन्द्र पिपराइच, सहायक अवर अभियंता बाढ़, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता नलकूप द्वितीय, सहायक अभियंता निर्माण खण्ड भवन, अवर अभियंता लघु सिंचाई, उप नगर आयुक्त नगर निगम, सहायक विकास अधिकारी, (पंचायत) खोराबार, पिपरौली, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) जंगल कौड़िया, खोराबार, भटहट, पिपरौली, पिपराइच, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उप श्रमायुक्त, आबकारी निरीक्षक, जिला प्रोवेशन अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जंगल कौड़िया भटहट, खण्ड विकास अधिकारी गण पिपरौली/चरगांवा, सहायक विकास अधिकारी (स0क0) खोराबार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी/कर्मचारियों एक दिन का वेतन बाधित करने के साथ ही स्पष्टीकराण देने का निर्देश देते हुए कहा कि स्पष्टीकरण संतोष जनक न होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने उप पुलिस महानिरीक्षक आनंद कुलकर्णी के साथ सदर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए दिये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में अधिकतर मामले राजस्व विभाग 116, पुलिस 20, विकास 4, समाज कल्याण विभाग 2 तथा अन्य विभाग 10 मामले आये, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।

इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी (सदर) मृणाली अविनाश जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें : संजय कुमार मीना

गोरखपुर। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को समय सीमा के अंदर ही निस्तारित करें।

उक्त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बन्धु एवं औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम की समीक्षा बैठक में दिया। गीडा से संबंधित निमार्णाधीन कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री सेक्टर 13, इंडस्ट्रियल/बिजनेस कॉरिडोर /लिंक एक्सप्रेस-वे-गोरखपुर आंचल में औद्योगिक विकास हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा, प्लास्टिक पार्क आदि का कार्य प्रगति पर है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उद्यमियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को ससमय करने का निर्देश दिया। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 10 आवेदन लंबित है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए सीडीओ ने योजना में शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि यथाशीघ्र लंबित आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों को तत्काल वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। बैठक में उद्यमियों द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थान नथमलपुर में वाटर सप्लाई, विकास नगर बरगदवां में स्थित बुद्धा फ्लोर मिल से आरटीएस एग्रो तक नाले एवं सड़क का निर्माण तथा औद्योगिक स्थान में स्ट्रीट लाइट की समस्या बताने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नगर निगम को समन्वय बनाकर समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।

साइबर क्राइम विषयक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

गोरखपुर । गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के सभागार में रोटी क्लब गोरखपुर द्वारा साइबर क्राइम पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने ऑनलाइन फ्रॉड व अन्य जागरुकता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करते हुए कहा कि साइबर क्राइम के होने वाले अपराधों से सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी।

नाली निर्माण के दौरान पुरानी दीवार गिरी मजदूर घायल एक नाजुक

गोरखपुर। में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया , नाले की खुदाई के दौरान बिजली ऑफिस की दीवार गिर गई । इस घटना में नाली निर्माण का काम कर रहे पांच मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना नॉर्मल इलाके की है ।वही घायल मजदूरों में घनश्याम, वीरु साहनी, प्रदीप, जोधन, अशोक शामिल रहे। इसमें प्रदीप को गंभीर चोटें आई हैं ।जानकारी के मुताबिक नगर निगम की नाली निर्माण के लिए खुदाई हो रही थी, तभी अचानक बिजली विभाग की पुरानी दीवार जो सन 2000 में बनाई गई थी वह गिर गई। दीवार के गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।,वही प्रशाशन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस हादसे के बाद अधिकारियों द्वारा इलाके में सुरक्षा को लेकर नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।

संविधान को लेकर लोगों को जागरूक होना होगा: प्रो.लक्ष्मण

कसया। नगर के सिसवा महंथ स्थित रामलीला मैदान में गत दिनों रविवार को संविधान दिवस मनाया गया। सांविधानिक मूल्यों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि संविधान को लेकर लोगों को जागरूक होना होगा। बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया। यदि नहीं चेते तो हजारों सालों तक चली सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म हो जाएगी। शिक्षा पर ध्यान दें और हक के लिए लड़ें। विशिष्ट अतिथि निर्देश सिंह, गुजरात आरक्षण आंदोलन के संयोजक चिराग पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, चंद्र भूषण सिंह यादव, डॉ. आरएस पटेल, डॉ. रमाकांत कुशवाहा, भंते डॉ. नंद रतन, भंते महेंद्र, प्रो. वीरेंद्र कुमार, भंते विमल कीर्ति, प्रो. बीडी गौतम, डॉ. अवधेश बौद्ध आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. राघवेंद्र सिंह पटेल, सह संयोजक सभासद विजेंदर सिंह भगत, कमलेश कुशवाहा आदि को पंचशील पट्टिका, संविधान की पुस्तक और बुद्ध कर प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला जज सगीर आलम ने की और संचालन नीतीश विश्वकर्मा व वृजेश कुशवाहा ने किया। डॉ. राघवेंद्र व विजेंद्र विश्वकर्मा ने आभार जताया।

सुमेर सागर ताल के सौंदर्यीकरण की परियोजना खटाई में

- निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू
- सितंबर 2023 से सुमेर सागर ताल सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया था
- दो सितंबर 2023 से लेकर एक जून 2024 तक सौंदर्यीकरण का काम पूरा करना था

गोरखपुर। सुमेर सागर ताल सौंदर्यीकरण की परियोजना फिलहाल खटाई में पड़ गई है। अदालत में लंबित मामले, कुछ हिस्से पर स्थनगन आदेश और शासन स्तर पर परियोजना के लिए धन स्वीकृत न किए जाने के अभाव में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब इस परियोजना को निरस्त करने का निर्णय लिया है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सितंबर 2023 से सुमेर सागर ताल सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया था।

रामगढ़ताल की तर्ज पर महानगरवासियों के लिए पयर्टन की दृष्टि से 18.50 एकड़ में विजय चौराहा से धर्मशाला बाजार के बीच फैले सुमेर सागर ताल के सौंदर्यीकरण की परियोजना बनाई थी। 27.74 करोड़ की रुपये की इस परियोजना की बोर्ड बैठक में स्वीकृति बाद एजेंसी मेसर्स प्रभा कांस्ट्रक्शन का चयन करते हुए वर्क आर्डर भी सौंप दिया। एजेंसी को दो सितंबर 2023 से लेकर एक जून 2024 तक सौंदर्यीकरण का काम पूरा करना था। परियोजना त्वरित आर्थिक विकास मद से बनाई गई थी। लेकिन, कई रिमांड के बाद शासन इस मद से ताल के सौदर्यीकरण का काम कराए जाने से इनकार कर दिया।

उच्चाधिकारियों की सलाह के बाद पयर्टन विभाग को भी परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी गई लेकिन वहां से भी परियोजना के लिए धन नहीं मिला। लिहाजा धनाभाव में वर्क आर्डर पाने वाली कंपनी ने चंद रोज काम करने के उपरांत परियोजना ठप कर दी। 29 नवंबर को प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में इस परियोजना को निरस्त करने का निर्णय लिया।

शासन और न्यायालय से मिले निदेशों के क्रम में परियोजना को फिलहाल निरस्त किया जा रहा है। जमीन को लेकर अदालतों में विवाद लंबित हैं, दूसरे त्वरित आर्थिक विकास परियोजना और पयर्टन विभाग से भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने से धन का अभाव भी है।

नरेंद्र कुमार,
अधिशासी अभियंता,
जीडीए

सुमेर सागर ताल की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण करते हुए लोगों ने पक्के मकान बना लिए थे। 2020 में तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल और तत्कालीन तहसीलदार डॉ. संजीव दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चला 10 एकड़ से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई। पांच अरब रुपये से अधिक की जमीन पर पक्के निर्माण तोड़े गए थे। तभी से ताल के जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही थी। ताल की जमीन पर अब भी अतिक्रमण है।

निजीकरण के विरोध में मुख्य अभियंता कार्यालय पर संघर्ष मोर्चा ने का ध्यानाकर्षण धरना

गोरखपुर। निजीकरण के विरोध में महानगर के मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कार्यालय के सामने विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समिति के पदाधिकारियों ने ध्यानाकर्षण धरना दिया। इस दौरान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिजली निगम के अलग-अलग संगठनों के विभिन्न गुट और पदाधिकारी भी दिखे।

घूँघट की बगावत

8 दिसम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सावधान : जी का जंजाल है साइबर फ्रॉड

पिछले दिनों कई लोगो को साइबर अरेस्ट किया गया। बहुतों से वसूली भी हुई। लूट का गिरोह सक्रिय है और आजकल नये नये तरीको से लूट का ऑनलाइन जाल बुनते है। एक पीड़िता नें बताया कि उन्होंने ऑनलाइन एक मैट्रिस ओएलएक्स पर बेचने के लिए डाला। प्रोडक्ट रीसेल का मेरा उनका यह पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने जैसे ही एड डाला वैसे ही तीन चार रिप्लाई आ गए कि कुछ लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। इतनी जल्दी रिप्लाई अमूमन आना नहीं चाहिए इसीलिए एक मैसेज देख दिमाग में खलबली मची। लिखा था कि वो कानपुर से हैं, मैट्रेस चाहिए, नंबर और डिटेल्स दीजिए। यूपी कि लोकल पार्टी देख उनके द्वारा नंबर दे दिया गया तो सामने से कॉल आया कि कानपुर किदवई नगर से बोल रहे हैं.. हम फर्नीचर और घरेलू सामान की मरम्मत कराकर रीसेल करते हैं। गद्दे की डील उन्होंने फाइनल कर दी और बोला कि मैम आप सेलिंग क्लोज कर दो, हम आदमी भेज रहे हैं गद्दा उठवाने के लिए, और पेमेंट के लिए मुझसे नंबर मांगा। मैं बैंक वाला नंबर शेयर नहीं करती सामने वाली सेलर महिला बोली , यूपीआई आईडी ही देती हूं, वो मैंने दे दिया। पहले तो उन्होंने बहस की कि इससे पेमेंट नहीं हो पायेगा, हमारा बिजनेस क्यूआर है, हम स्वाईप मशीन से पैसा भेजते हैं.. आप गूगल पे नंबर दीजिए। मेरे पास जी पे नहीं है तो सेलर महिला नें कहा जीपे हो या कोई भी ऐप, यह सबपे काम करती है, मैं ऑल इंडिया से पेमेंट मंगाती हूं इसी पे.. फिर वो बोला देखते हैं, फिर बताया कि हो जायेगा पर हम पहले आपको 1₹ भेजकर कन्फर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है कर लो। थोड़ी देर बाद सामने आई उस साइबर ठग कि असल चाल, उसने एक क्यू आर कोड भेजा और बोला मैम इसको स्कैन कर लो पेमेंट रिसीव करने के लिए। महिला नें जब उस कोड को स्कैन किया तो उसमें नेक्स्ट स्टेप पिन भरने का आने लगा, उसने तुरंत रोक दिया और कहा कि ये गलत है नादान हूँ पर मुर्ख नहीं , इसमें मुझे पैसा मिलेगा नहीं बल्कि मेरे अकाउंट से कटेगा। वो बहन बहन करने लगा और बोला क्या बात कर रही हो मेरी बहन, आप कोड देखो, उसपे रिसीव मनी लिखा है कि नहीं। आप ट्रस्ट करो। महिला ने साफ मना किया कि कोई भी तरीका हो मैं अपना पिन नहीं डालूंगी, जब पैसा भेजना होता है तब ही पिन डालना होता है। वो बोलने लगा आपने कभी बिजनेस क़्यू आर स्वाइप मशीन से पैसे नहीं लिए क्या.. मैने कहा नहीं, तो बोला तभी तो कह रहा हूं ऐसे ही होता है बहन, कृपया आप आगे की प्रोसेस करो, ताकि मैं आगे आपको 1500 रूपए मेट्रिस का भेज सकूं। महिला समझ चुकी थी ये फ़्रॉड है, बिना प्रोडक्ट देखे कोई भी पेमेंट नहीं भेजता।महिला ने कह दिया गद्दा आप लो या न लो, मैं 1 रुपया क्या 1500 रुपए लेने के लिए भी अपना पिन नहीं डालने वाली। गद्दा अगर वाकई लेना है तो आप जब गद्दा लेने के लिए जो अपना बंदा भेजें उसे ही पेमेंट दे दें। तो वो आदमी मुझ पे चिल्लाने लगा कि बकवास करती हो आप, मेरे अकाउंट से 1500 का पेमेंट आपने ले लिया क्यूआर के थ्रो वो कौन देगा ? महिला को गुस्सा आ गया, मैंने कहा अच्छा, मैंने पेमेंट ले लिया बिना आपके भेजे.. सुनो, अब तुमको अब पुलिस देगी पेमेंट, बस तभी कॉल कट गई.. मुझे उस नंबर से व्हाट्सएप और हर जगह ब्लॉक कर दिया गया। इन फैक्ट वह नंबर ही बंद कर दिया गया। पापा के फोन से टॉय किया तो भी वो नंबर मिला नहीं। दोस्तों, बस एक सतर्कता की वजह से, मेरा अकाउंट खाली होते बच गया। मैं अगर उस रिसीव वाले क्यूआर पर अपना यूपीआई पिन डालकर कन्फर्म कर देती तो जितनी रकम उसने भरी होती वो सब उसके पास चली जाती, और फिर वो नंबर बंद कर लेता। डिटेल तो ओब्वियस्ली उसने झूठ दिया ही होता, मान लो बैठा होता पंजाब में तो कानपुर के किदवई नगर में तो उसे कैसे भी नहीं ढूंढ सकती थी। असल में पैसे रिसीव करने के लिए कोई क्यूआर नहीं होता। क्यूआर का मतलब ही है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये लोग पैसे लेने के लिए क्यूआर जनरेट करते हैं, और फिर इमेज में एडिट करके रिसीव मनी लिख देते हैं, आपको दिखेगा रिसीव मनी, पर वो क्यूआर होगा सेंड मनी का। क्यूआर का डिजाइन देखकर आप नहीं पहचान सकते, लेकिन मोबाइल रीड कर लेता है और आपको यूपीआई पिन डालने के लिए कहता है। हमेशा याद रखें, कभी भी पैसा लेने के लिए आपको अपना पिन नहीं डालना है, किसी भी मर्चेंट/बिजनेस क्यूआर का फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्टिंग के लिए आपको अपना पिन नहीं डालना है। 1 रुपए के लिए भी नहीं डालें आप। जरूरी नहीं उपर रिसीव 1₹ प्रिंट दिख रहा हो लेकिन वो क्यूआर सेंड 25000 रुपए करेगा। महिला को यह बात पता थी, तो उसनें नहीं डाला और पैसे गंवाने से बच गई। जैसे ही कोई आपको पैसे मिलने के लिए क्यूआर भेजे तभी सतर्क हो जाएं। ये लोग -₹ऐसे नहीं हो पायेगा पेमेंट, वैसे नहीं हो पायेगा₹...या यह डिटेल दीजिए.. वह डिटेल दीजिए₹.. कहकर दिमाग काट देते हैं और फिर व्यक्ति इनके कहे अनुसार ही स्टेप्स फॉलो करने लगता है। कोई व्यक्ति कितनी भी हड़बड़ी मचाए, आप अपना दिमाग चालू कर लें, और आपको उसके बताए स्टेप्स पर बिल्कुल नहीं चलना है। एक बात और, कोई भी पुराना सामान बिना देखे, बिना उसकी कंडीशन चेक किए, सिर्फ.फोटो के आधार पर अजनबियों से कोई नहीं खरीदता है

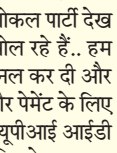

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर

सकारात्मक शिक्षण स्थानों के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका

शिक्षक एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण का पोषण करके इसे संभव बनाने में प्रमुख उत्प्रेरक हैं जो छात्रों को उनकी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, सोच-समझकर जुड़ने और मील के पत्थर को मनाने के लिए रणनीतियों को लागू करके, शिक्षक एक शैक्षिक माहौल स्थापित कर सकते हैं जो प्रगति, आत्म-सम्मान और टीम वर्क का समर्थन करता है।

एक सफल कक्षा केवल किताबों और संसाधनों के बारे में नहीं है; यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां छात्र सफल होने के लिए मूल्यवान, सुने जाने वाले और सशक्त महसूस करते हैं एक संपन्न शिक्षण कक्षा का आधार इस बात पर आधारित होता है कि छात्र अपनी कक्षा को किस तरह से समझते हैं। यह केवल उचित संसाधनों का उपयोग करने के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह स्थापित करने के बारे में है जहां छात्र मान्यता प्राप्त, सुने जाने वाले और मूल्यवान महसूस करें। शिक्षक एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण का पोषण करके इसे संभव बनाने में प्रमुख उत्प्रेरक हैं जो छात्रों को उनकी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, सोच-समझ-ाकर जुड़ने और मील के पत्थर को मनाने के लिए रणनीतियों को लागू करके, शिक्षक एक शैक्षिक माहौल स्थापित कर सकते हैं जो प्रगति, आत्म-सम्मान और टीम वर्क का समर्थन करता है।

शिक्षक एक सकारात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण स्थान बना सकते हैं: प्रत्याशा की भावना विकसित करें

शिक्षकों को अपने छात्रों को स्पष्ट निर्देश और प्र-क्रियाएँ देनी चाहिए ताकि वे सहज महसूस करें। जब छात्रों को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, तो पाठ के साथ उनकी बातचीत बढ़ जाती है और उनकी सीखने की क्षमताओं में उनका विश्वास बढ़ जाता है, जिससे उनका मूड शांत और केंद्रित हो जाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को संबोधित करें। कक्षा में कोई भी छात्र पूरी तरह से दूसरे के समान नहीं होता है। प्रशिक्षकों को शैक्षणिक और भावनात्मक जरूरतों की सराहना करनी चाहिए और सामग्री, ध्यान और प्रेरणा के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कक्षा में शिक्षार्थियों का स्वागत करें पहली छाप बहुत मायने रखती है। एक सरल मुस्कुराती हुई सुबह की शुभकामनाएं छात्रों को प्राप्त होती हैं और दिन का इंतजार करती हैं। एक स्वागत योग्य वातावरण कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और भागीदारी का कारण बनता है। छात्रों के साथ बातचीत करें आदर्श रूप से, इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच एक शक्तिशाली स्नेह तैयार करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों को छात्रों के जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए; उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए और उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए। इससे विश्वास पैदा होता है, पढ़ने का कौशल विकसित होता है और छात्र अधिक बोलना चाहते हैं। टीम-निर्माण गतिविधियाँटीम-निर्माण गतिविधियाँ निदेर्शों का अभ्यास करने और दूसरों के प्रति प्रशंसा दिखाने में मदद करती हैं। अनुभवशील बनें कभी-कभी, शिक्षकों की गलतियाँ, असफलताएँ और हानियाँ सीखने के माहौल को आरामदायक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को जुड़ने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो दशार्ता है कि सीखना सामूहिक है और व्यक्तिगत नहीं।

सफलता का जश्न मनाएं और छात्रों की सराहना करें

छात्रों की उपलब्धियों को पहचानने और उनका जश्न मनाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षकों को ऐसे व्यवहार को कक्षा में मौखिक प्रशंसा, पुरस्कार या अन्य प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत करना चाहिए। निर्णय से बचें: अनुकूल सीखने के माहौल में स्वीकार्यता और खुली मानसिकता स्पष्ट होती है। निर्णय को छात्रों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सकें और बिना हँसे गलतियाँ भी कर सकें।

क्रोध को दबाएँ और रणनीतिक ढंग से कार्य करें

शिक्षकों से भावनात्मक विनियमन की अपेक्षा की जाती है। संघर्षों या समस्याओं के दौरान शांत रहना छात्रों की भावनाओं और समस्या-समाधान कौशल के लिए एक अच्छी मयार्दा के रूप में कार्य करता है, यह अभ्यास एक सीखने के माहौल की ओर ले जाता है जो शांत और लक्ष्य-उन्मुख होता है। उनके विचार सुनें छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देने से उन्हें अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षकों को छात्रों को अपने मन की बात कहने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

फीडबैक स्वीकार करें:

शिक्षकों को किसी भी फीडबैक को प्रोत्साहित करना चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिएउनके छात्रों से. यदि छात्रों की प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना की जाती है, तो माहौल संवादात्मक बन जाता है। कमरे को व्यवस्थित करना, छात्रों की देखभाल करना या उपलब्धि को पहचानना जैसी सरल गतिविधियां शिक्षकों को छात्रों के लिए एक सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य स्थान डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक स्वागत योग्य और पोषित कक्षा शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि और भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाती है

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

खतरनाक होता बायोमेडिकल वेस्ट

स्वास्थ्य सेवा गतिविधियाँ स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और उसे बहाल करती हैं तथा जीवन बचाती हैं। लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट और उप-उत्पादों के बारे में क्या? स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से लगभग 85% सामान्य, गैर-खतरनाक अपशिष्ट है जो घरेलू अपशिष्ट के बराबर है। शेष 15% को खतरनाक सामग्री माना जाता है जो संक्रामक, रासायनिक या रेडियोधर्मी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उपाय ऐसे अपशिष्टों से होने वाले प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को रोक सकते हैं, जिसमें रासायनिक या जैविक खतरों का अनपेक्षित उत्सर्जन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों में संभावित रूप से हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो अस्पताल के रोगियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता को संक्रमित कर सकते हैं। अन्य संभावित खतरों में दवा प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव शामिल हो सकते हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से पर्यावरण में फैलते हैं। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट और उप-उत्पादों से जुड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों में तीक्ष्ण वस्तुओं से लगी चोटें भी शामिल हैं; स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के संचालन या भस्मीकरण के दौरान आस-पास के वातावरण में छोड़े जाने वाले दवा उत्पादों, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स और साइटोटॉक्सिक दवाओं और पारा या डाइऑक्सिन जैसे पदार्थों के संपर्क में आना; कीटाणुशोधन, बंध्यीकरण या अपशिष्ट उपचार गतिविधियों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली रासायनिक जलन; चिकित्सा अपशिष्ट भस्मीकरण के दौरान कण पदार्थ के निकलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण; खुले में जलने और चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक के संचालन के साथ होने वाली तापीय चोटें; विकिरण जलन; और दवा अपशिष्टों के असुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध का प्रसार। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट सेवाओं के लिए कई कारण मौजूद हैं। इनमें सीमित कानूनी ढाँचे (जैसे, नीतियाँ, विनियमन, दिशा-निर्देश), स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट से सम्बंधित स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता की कमी, उचित अपशिष्ट प्रबंधन में अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रणालियों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन और कम प्राथमिकता शामिल हैं। कई देशों में या तो उचित नियम नहीं हैं या वे उनकी निगरानी और प्रवर्तन नहीं करते हैं।

दुनिया भर में, हर साल अनुमानित 16 बिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सभी सुइयों और सिरिंजों का सुरक्षित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, जिससे चोट और संक्रमण का जोखिम और दोबारा इस्तेमाल के अवसर पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दूषित सुइयों और सिरिंजों से इंजेक्शन लगाने में काफी कमी आई है, आंशिक रूप से इंजेक्शन उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल को कम करने के प्रयासों के कारण। इस प्रगति के बावजूद,

स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से लगभग 85% सामान्य, गैर-खतरनाक अपशिष्ट है। शेष 15% को खतरनाक सामग्री माना जाता है जो संक्रामक, विषाक्त, कैंसरकारी, ज्वलनशील, संक्षारक, प्रतिक्रियाशील, विस्फोटक या रेडियोधर्मी हो सकता है। हर साल दुनिया भर में अनुमानित 16 बिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन सभी सुइयों और सिरिंजों का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों को खुले में जलाने और कम तापमान पर जलाने से, कुछ परिस्थितियों में, डाइऑक्सिन, फ़्यूरान और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन हो सकता है।

असुरक्षित इंजेक्शन अभी भी 33, 800 नए एचआईवी संक्रमण, 1.7 मिलियन हेपेटाइटिस बी संक्रमण और 315, 000 हेपेटाइटिस-सी संक्रमण के लिए जिम्मेदार थे। संक्रमित स्रोत रोगी पर इस्तेमाल की गई सुई से एक व्यक्ति को सुई लगने से चोट लगने का अनुभव होने पर उसे एचबीवी, एचसीवी और एचआईवी से संक्रमित होने का क्रमशः 30%, 1.8% और 0.3% जोखिम होता है। अपशिष्ट निपटान स्थलों पर सफाई करने और स्वास्थ्य सुविधाओं से खतरनाक अपशिष्ट को संभालने और मैन्युअल रूप से छांटने के दौरान अतिरिक्त खतरे उत्पन्न होते हैं। ये प्रथाएँ दुनिया के कई क्षेत्रों में आम हैं, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। अपशिष्ट संचालकों को सुई चुभने की चोट लगने और विषैले या संक्रामक पदार्थों के संपर्क में आने का तत्काल जोखिम होता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट का उपचार और निपटान पर्यावरण में रोगजनकों और विषैले प्रदूषकों के निकलने के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। लैंडफिल में अनुपचारित स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के निपटान से पीने, सतह और भूजल का संदूषण हो सकता है, अगर उन लैंडफिल का निर्माण ठीक से नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों को कम से कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे उस अपशिष्ट की मात्रा में काफी कमी आएगी जिसे संभालने और उपचारित करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट न्यूनीकरण क्रियाओं में हरित खरीद और ऐसे उत्पादों का चयन करना शामिल है जहाँ शिपिंग कम से कम हो और कम और पारिस्थितिक पैकेजिंग हो, सुरक्षित और व्यवहार्य होने पर पुनः प्रयोज्य उत्पादों पर स्विच करना, केवल प्रलेखित आवश्यकता के आधार पर फार्मास्यूटिकल्स का ऑर्डर देना / प्राप्त करना और प्लास्टिक, कागज और कार्डबोर्ड सहित सामान्य वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना शामिल है। रासायनिक कीटाणुनाशकों के साथ स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के उपचार के परिणामस्वरूप पर्यावरण में रासायनिक पदार्थ निकल सकते हैं यदि उन पदार्थों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संभाला, संग्रहीत और निपटाया नहीं जाता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अधिक ध्यान और परिश्रम की आवश्यकता होती है, ताकि खराब अभ्यास से जुड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से बचा जा सके, जिसमें संक्रामक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रमुख तत्व हैं उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम करते हैं और उचित अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करते हैं; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के अंतिम उद्देश्य के साथ अपशिष्ट पृथक्करण, विनाश और निपटान प्रथाओं में क्रमिक रूप से सुधार करने के लिए मजबूत निगरानी और विनियमन के साथ-साथ रणनीति और प्रणाली विकसित करना; जहाँ संभव हो, चिकित्सा अपशिष्ट भस्मीकरण की तुलना में खतरनाक स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल उपचार (उदाहरण के लिए, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, आंतरिक मिश्रण के साथ एकीकृत भाप उपचार और रासायनिक उपचार) का पक्ष लेना; एक व्यापक प्रणाली का निर्माण, जिम्मेदारियों, संसाधन आवंटन, तथा अपशिष्ट को एकत्रित करने, संभालने, भंडारण करने, परिवहन करने, उपचारित करने या निपटाने के दौरान लोगों को खतरों से बचाने के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन विकल्पों का चयन करना। सार्वभौमिक, दीर्घकालिक सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और समर्थन की आवश्यकता है, हालांकि स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

बांग्लादेश की हरकतें निंदनीय

भगवा से बचे,तुलसी की माला छिपाएं और तिलक न लगाएं खबर पढ़ी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यको व इस्कान के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह इस्कान कोलकाता द्वारा दी जा रही है।धर्मनिरपेक्षता का हमारे देश में शांति पूर्ण,मैत्रीयता, का पालन होता है वैसा बांग्लादेश में कहाँ होता है।सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया ही वहां की घटनाओं का सच उजागरकरती आ रही है।अगर ये उजागर नही करती तो वहाँ रह रहे साधु -संतों एवं हिंदू अल्पसंख्यको को धमकी ,हिंसा की हो रही घटनाओं का पता भी नही चलता।कुछ दिनों पूर्वबांग्लादेश में अराजकता ,अब भारतीय बस पर हमला खबर पढ़ीबांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अब कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जोकि उचित हैं महज घटना की निंदा करने से काम चलने वाला नहीं हैं वहां के प्रशासन से भारतीय लोगो की सुरक्षा हेतु सख्त निर्देश प्रशासन को देबांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से ज्यादा बाद ज्यादा बढ़ गयो बांग्लादेश में अब तक हिंदू आबादी कम ही हुई है `जिसका प्रमुख कारण हत्या,अपहरण ,धमकी,धर्म परिवर्तन आदि से हिंदू आबादी का प्रतिशत काफी कम हुआ। सत्तर के दशक में पाकिस्तानी सेना के काफी अत्याचार से बांग्ला देशी लोग भारत में किसी भी तरीके से आने को मजबूर हुऐ पाकिस्तान यही चाहता था कि यहाँ का मत प्रतिशत गड़बड़ा जाऐआधार कार्ड के फजीर्वाड़ा की घटनाएं भी सामने आई थीं सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर धमकी ,अत्याचार एवं नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन व ,सभी देशो की होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में यह मुद्दा क्यों नही उठाया जा रहा है ?जबकि भारत देश हमारा विश्व शांति ,मैत्रीयता,अहिंसा , सहयोग हेतु सदैव अग्रणी रहा जिसका लोहा आज कई देश भी मान रहे हैं बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार, धमकी और नरसंहार पर अंकुश लगाया जाऐ भविष्य में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की तरह व्यवहार किया जावेगा

संजय वर्मा 'दृष्टि'
मनावर जिला धार मप्र

अभिभावकों को मोबाइल की लत

विजय गर्ग

बच्चे तो बच्चे अभिभावकों को भी मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। माता-पिता और बच्चों का मजबूत रिश्ता बनाने में स्मार्टफोन बाधक बन रहा है। देश के 76 प्रतिशत बच्चे तो 84 प्रतिशत अभिभावक एक-दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं. लेकिन स्मार्ट-फोन और इंटरनेट मीडिया उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। तभी 94 प्रतिशत बच्चे चाहते हैं कि उनके माता-पिता के स्मार्टफोन में कालिंग, मैसेजिंग और कैमरा जैसे सिर्फ तीन फीचर होने चाहिए। बच्चे नहीं चाहते हैं कि माता-पिता के स्मार्टफोन में इंटरनेट मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग एप की सुविधा हो। दूसरी तरफ 75 प्रतिशत अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे स्मार्टफोन की लत की वजह से परिवार के साथ सार्थक रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं। परंतु बच्चे और अभिभावक दोनों ही स्मार्ट-फोन की आदत छोड़ने को तैयार नहीं हैं। स्मार्टफोन निमार्ता कंपनी वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च की तरफ से अभिभावक बच्चों के रिश्तों पर स्मार्टफोन का असर संबंधी अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। वीवो स्विच आफ 2024' सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिभावक रोजाना औसतन पांच घंटे से अधिक तो बच्चे चार घंटे स्मार्टफोन पर अपना समय व्यतीत करते हैं। दोनों अपना अधिकतर समय इंटरनेट मीडिया और एंटरटेनमेंट एप पर बिताते हैं।

76 प्रतिशत अभिभावक और 71 प्रतिशत बच्चों ने सर्वे के दौरान यह माना कि वे स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं। 64 प्रतिशत बच्चे मानते हैं कि उन्हें स्मार्टफोन की बुरी लत लग चुकी है। 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने बताया कि अगर उनके दोस्त इंटरनेट मीडिया एप से हट जाएं तो वे भी इसका उपयोग छोड़ सकते हैं।

आदमी कितना बदल गया

आदमी कितना एहसान फरामोश हो गया
अपने ही नशे में मदहोश हो गया
मिलते हुए भी जिन्दगी में सब कुछ
दिल से क्यों खानाबदोश हो गया

तिरछी नजरों से ताकता है सब को
सामने से नजर क्यों मिलाता नहीं
दिल में दबाकर रखता है सारी बातें
पूछने पर भी क्यों बताता नहीं

भेद रखता है सभी के
बाहर से क्यों बनता है अनजान
घर बनाना अब भूल गया
बनाये जा रहा नए नए मकान

करने लगता है नेकी की बातें
किसी के साथ जब जाता है शमशान
लौटने पर फिर सब कुछ है भूल जाता
खोल देता है फिर बेईमानी और पैसे की दुकान

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना

गोरखपुर। में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे थे. यह रैली फातिमा हॉस्पिटल ने निकाली थी। इस रैली में गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और विशप मैथ्यू नेलिकुलेन भी शामिल हुए थे. यह रैली चेतना तिराहे, गोलघर से शुरू हुई थी और ए आर टी सेंटर जिला अस्पताल पर खत्म हुई थी। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है. इस दिन को एड्स से मरने वाले लोगों के स्मरणोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महामारी से प्रभावित लोगों को सम्मानित करना है।

विश्व मृदा दिवस : उर्वरता खोते झांसी के खेत

झांसी। झांसी की मिट्टी बीमार हो गई है। इससे महत्वपूर्ण पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। यह खुलासा कृषि विभाग की प्रयोगशाला में हुई जांच में हुआ है। इसमें सामने आया है कि जिले की मिट्टी में जीवाश्म कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी है। इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से यह स्थिति पैदा हुई है।

कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पद्धति से मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है। इसके बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर नवंबर माह तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों की मिट्टी के 11,913 नमूनों की जांच की गई, जिनमें जीवाश्म कार्बन की मात्रा 0.42 से 0.68 प्रतिशत पाई गई, जबकि अच्छी मिट्टी में यह एक प्रतिशत या इससे अधिक होता है।

इसी प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेअर में 280 किलोग्राम से कम पाई गई। जबकि, मिट्टी में 280 से 560 किलो तक नाइट्रोजन की मात्रा मध्यम और 560 से अधिक उच्च मानी जाती है। इसी प्रकार मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा प्रति हेक्टेअर में 10 किलोग्राम से भी कम पाई गई। यह बेहद निम्न श्रेणी है। सेहतमंद मिट्टी में 20 से 40 किलोग्राम तक फास-फोरस का होना जरूरी होता है।

मिट्टी में अवयवों की भूमिका

जीवाश्म कार्बन : इसे मिट्टी का हीमोग्लोबिन माना जाता है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है। मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखता है। मिट्टी में भुरभुरापन बनाए रखता है। पौधों को पोषण प्रदान करता है।

नाइट्रोजन : पौधों की बढ़त में नाइट्रोजन की सबसे अहम भूमिका होती है। मिट्टी में इसकी प्रचुर मात्रा से उपज भी अच्छी होती है।

फास्फोरस : पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। बीज बनाने में मदद करता है। बीज की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाकर मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं। जांच के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा भी लोग अपने खेत की मिट्टी की प्रयोगशाला में जांच करा सकते हैं। मुख्य तत्वों की जांच का शुल्क विभाग द्वारा 29 रुपये लिया जाता है। जबकि, मुख्य तत्व व अन्य सूक्ष्म तत्वों की जांच का शुल्क 102 रुपये अदा करना होता है। जांच के लिए आधा किलोग्राम मिट्टी देनी होती है। मिट्टी सूखी होने पर एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट दे दी जाती है। जांच रिपोर्ट के साथ किसानों को मिट्टी को सेहतमंद बनाने के उपाय भी बताए जाते हैं।

> रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। जांच के बाद किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी बताए जाते हैं।
>
> - एमपी सिंह, उप निदेशक कृषि

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को कमजोर करार देता पड़ोसी देश

भारत के साथ नेपाल के संबंधों पर प्रकाश डाला जाए तो हाल में नेपाल ने भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली बेची है, जो क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण पहल है। बांग्लादेश को बिजली बेचने से नेपाल को न केवल आर्थिक फायदा होगा, बल्कि उसके लिए भारत के रास्ते अन्य देशों को भी बिजली बेचने के रास्ते खुलेंगे। भारत और नेपाल पनबिजली क्षेत्र में एक और मजबूत साझेदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

चूंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एक सामान्य बात है और हर छह-आठ महीनों में एक नई सरकार आती है, ऐसे में हर प्रधानमंत्री का भारत आना नेपाली विदेश नीति के लिए दूसरे पड़ोसी देश की अनदेखा करने का संकेत माना जा सकता है। इससे उसके हित प्रभावित हो सकते हैं। यहां यह भी देखना जरूरी है कि ओली नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन वाली सरकार चला रहे हैं और नेपाली कांग्रेस भारत के साथ मजबूत संबंधों की वकालत करती रही है।

चूंकि मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री नेपाली कांग्रेस से हैं, ऐसे में नेपाली कांग्रेस भारत के साथ इतना बड़ा जोखिम लेने से बचेगी। इसलिए नेपाल दो पड़ोसियों के बीच संतुलित विदेश नीति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओली का चीन के प्रति झुकाव नेपाल के लिए फायदे का सबब बना है? उत्तर नकारात्मक ही है, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच जितने भी बड़े समझौते पिछले दस वर्षों में हुए हैं, उनमें ज्यादातर ठंडे बस्ते में पड़े हैं और यह बात चीन को सताती रही है। मई 2017 में चीन ने नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआर-आई) पर समझौता किया, जिसे चीन की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा गया, क्योंकि भारत लगातार बीआरआई के अंतर्गत बने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आलोचना करता रहा है। बीआरआई समझौते के तहत चीन को नेपाल में बड़े बुनियादी ढांचे वाली तमाम परियोजनाओं में निवेश करना है, जिनमें ट्रांस-हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क खास है, जो नेपाल को रेल एवं सड़क मार्ग से तिब्बत प्रांत से जोड़ने वाला है। इससे ऐसा लगा कि नेपाल चीन के रास्ते भारत पर अपनी निर्भरता कम करने का मार्ग खोज रहा है, लेकिन करीब सात वर्ष बीत जाने के बाद भी नेपाल में ऐसी एक भी परियोजना लागू नहीं हो सकी है।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं। इस यात्रा को नेपाल को चीन के और नजदीक ले जाने का सूचक माना जा रहा है, क्योंकि परंपरागत तौर पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पहली विदेश यात्रा पर भारत आते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विरोध और चीन से मित्रता ओली की व्यक्तिगत रुचि रही है।

ओली हमेशा चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने भारत विरोध का सहारा लेकर ही अपनी राजनीति मजबूत की है, फिर चाहे वह 2015 में की गई सीमा की नाकाबंदी हो, 2019 में सीमा-विवाद का राजनीतीकरण करना हो या फिर नेपाल का एक विवादित नक्शा लाना हो, जिसमें नेपाल ने भारत के कुछ संप्रभु क्षेत्रों को अपना दिखाया।

ओली का राजनीतिक झुकाव चीन की ओर होना भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन उनकी इस यात्रा को नेपाल का भारत से दूर जाना मान लेना भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को कमजोर करार देने के बराबर है। तथ्य बताते हैं कि जितनी भी बार ओली और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एमाले) ने चीन के साथ समझौते या राजनीतिक संबंधों की वकालत की है, वह मुख्यतः प्रतीकात्मक ही रही है और परिणामों पर कम खरी उतरी है।

इसके दो कारण हैं। पहला, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के चलते परियोजनाओं की पहचान नहीं हो पाई है। दूसरा, नेपाल लगातार चीन से बीआरआई के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग वित्तीय सहायता के तौर पर चाहता है। जबकि चीन कर्ज देने में रुचि रखता है। श्रीलंका का उदाहरण देखते हुए नेपाल इससे डर रहा है। बड़े कर्ज के चलते श्रीलंका को अपने हंबनटोटा जैसे बंदरगाह का नियंत्रण चीन के हाथों में देना पड़ा है।

अगर नेपाल चीन से कर्ज लेता है तो भविष्य में उसे नेपाल पर दबाव बनाने का अवसर मिलेगा, जो बीआरआई का मुख्य वैश्विक उद्देश्य रहा है। वर्ष 2016 में ओली ने अपनी चीन यात्रा के दौरान उसके साथ परिवहन एवं परिगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत नेपाल चीन के छह बंदरगाहों के रास्ते अन्य देशों से व्यापार कर सकता है।

नेपाल पूरब में चीन से और तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। वह भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर अन्य देशों से व्यापार करता रहा है। यह उसके लिए हर तरह से फायदेमंद है, लेकिन 2015 में भारत के साथ सीमाबंदी का मुद्दा सामने आने के बाद ओली ने चीन को एक विकल्प के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो चीन के बंदरगाह नेपाल से कम से कम 3,000 किलोमीटर दूरी पर हैं। जबकि भारत का कोलकाता बंदरगाह मात्रा 700 किलोमीटर दूर है। समझौते के छह साल बाद भी नेपाल ने चीन के बंदरगाहों के रास्ते केवल एक ही बार व्यापार किया है। इसकी वजह यह है कि नेपाल के लिए भारत के रास्ते व्यापार करना आसान और किफायती है।

औषधि विभाग की छापेमारी

एक्सपायर दवाओं का जखीरा बरामद

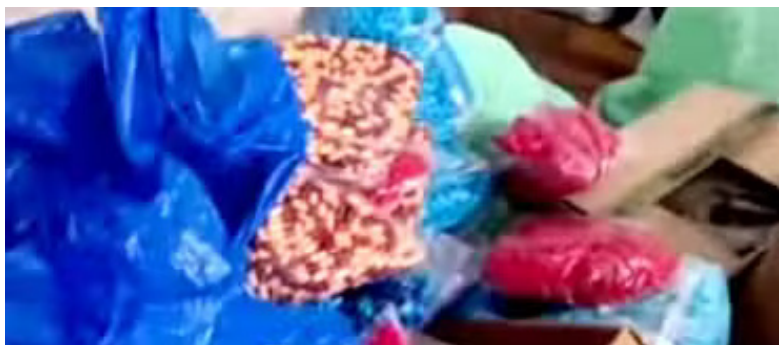

इटावा। शहर के सराय शेख में छह दिन पहले गुप्ता फार्मा एंड कंपनी में गैर प्रांतों की फार्मा कंपनियों की एक्सपायर दवाओं का जखीरा औषधि विभाग की छापेमारी में मिला था। औषधि विभाग की जांच में पता चला है कि ये दवाएं दर्द निवारक, एंटी एलर्जी, एंटी बायोटिक, शक्तिवर्धक, मदार्ना कमजोरी की दूर करने की थी। इनकी खपत भी अधिक थी। डीआई रजत ने गुप्ता फार्मा एंड कंपनी से इस मामले में बिल मांगे थे, इसके लिए उन्हें सात दिन का समय दिया था। पांच दिन बीत जाने के बाद भी संचालक ने अभी तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। औषधि निरीक्षक रजत पांडेय ने बताया कि गुप्ता फार्मा एंड कंपनी के संचालक राजीव कुमार गुप्ता इन दवाओं को मिक्सर में पीसकर लाल, हरे, पीले, नीले, काले, सुनहरे कैप्सूल बनाकर बेचता था। डीआई ने बताया कि नोटिस के सात में से पांच दिन बीत गए हैं। यदि समय पर जवाब नहीं मिला तो डीएम की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता फार्मा एंड कंपनी में छापे के दौरान छह हजार सुनहरे कैप्सूल मिले थे। औषधि विभाग के अनुसार इन कैप्सूलों में मदार्ना कमजोरी को दूर करने वाली दवा भरी थे, जिन्हें आयुर्वेदिक का नाम देकर एक कैप्सूल को 80 रुपये में दिया जा रहा था, जो मरीज को 100 रुपये में पड़ता था। लखनऊ भेजे के सैंपल में पता चलेगा यह कितना कारगर था या मरीजों को इसके खाने से नुकसान होगा। यह बात जांच रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। लाल रंग के कैप्सूल में दर्द निवारक और काले रंग के कैप्सूल में गैस की दवा रहती थी। इसी तरह पीले और भूरे कैप्सूल एंटी बायोटिक होने के बताए गए हैं। हरे रंग में एंटी एलर्जी, गुलाबी रंग के कैप्सूल में शक्तिवर्धक दवा थी।

सांसद राजीव राय ने सदन में उठाई आवाज

'भोजपुरी भाषा के संगे सौतेला व्यवहार बरदाश्त ना होई'

घोसी। घोसी लोकसभा से सपा के सांसद राजीव राय ने मंगलवार को भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनसूची में शामिल करने के लिए लोक सभा के सदन में भोजपुरी से ही अपने कथन की शुरूआत किया।

सांसद राजीव राय ने कहा कि संविधान के आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा के शामिल करे खातिर आज लोकसभा में नियम 377 के अधीन नोटिस देनी ह! अब मंत्री जी के जबाब क इंतजार बा। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले वाले भाषा के संगे सौतेला व्यवहार बरदाश्त ना होई।

कहा कि भोजपुरी भाषा हजारों साल पुरानी है, इस-की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और यह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे कैथी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन 1894 से देवनागरी लिपि ने इसे मुख्य लिपि के रूप में स्थान दिया। भोजपुरी का साहित्य भी समृद्ध है, जिसमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, विवेकी राय और भिखारी ठाकुर जैसे लेखकों की कृतियां शामिल हैं। हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख लेखक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद भी भोजपुरी साहित्य से गहरे रूप से प्रभावित थे।

कहा कि भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है, साथ ही यह मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल जैसे देशों में भी महत्वपूर्ण प्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। अनुमान है कि भारत में 50 मिलियन से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं, जिससे यह देश की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 28.50 लाख से अधिक है। भोजपुरी फिल्में भारत और विदेशों में लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म उद्योग पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि भोजपुरी को यूनेस्को के भाषा विश्व एटलस में एक संकटग्रस्त भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो हिंदी के प्रभाव और सरकार की निरंतर उपेक्षा के कारण है। सांसद राजीव राय बोले कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबित मांग है, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी भाषा आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं पा सकी है, जबकि सरकार ने इसके लिए वादे किए थे।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बूंदाबांदी के आसार

लखनऊ। राजधानी में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। रविवार व सोमवार को बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से बूंदाबांदी के साथ दिन के पारे में दो डिग्री तक की गिरावट से ठंड बढ़ेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि दो से तीन दिनों में रात के पारे में 2 से 3 डिग्री तक के उछाल की संभावना है। इसके बाद पारे में फिर गिरावट आएगी। शनिवार को पछुआ के सुस्त होने के बाद भी सुबह-शाम की हवा में सिहरन महसूस की गई। दिन का तापमान 25.7 डिग्री के साथ स्थिर रहा तो रात का पारा 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती आधी आबादी

संयुक्त राष्ट्र ने हाल में महिला आधारित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2050 तक जलवायु परिवर्तन के चलते 158 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां गरीबी की ओर जा सकती हैं। वहीं 236 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।

एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 130 मिलियन लड़कियों को शिक्षा के मानवाधिकार से वंचित रखा जाता है और जलवायु संबंधी संकट इस दिक्कत को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे मुश्किल समय में लड़कियों की जल्दी शादी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उन्हें घर की जरूरतों में मदद करने के लिए सबसे पहले स्कूल से निकाला जाता है। जलवायु संकट, क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग और अथाह वायु प्रदूषण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है, उनका सबसे अधिक सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पूरी दुनिया में मां की कोख में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में बिखरे हैवी मेटल्स मां की सांस के जरिए अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण नवजातों के दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए घातक है। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर पॉल्यूशन प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच रहा है। इससे शिशु के दिमाग और फेफड़े सही से विकसित नहीं हो पाते हैं। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण महिला स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, एचआईवी-एड्स, मलेरिया और टीबी के लिए हर साल बड़े वैश्विक कोष का निवेश किया जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिहाज से ऐसा नहीं है। यह जमीनी हकीकत है कि-जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर गहरे तक पड़ने वाला प्रभाव संवेदनशील मुद्दा है। जागरूकता फैलाने, शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच प्रदान करने, आर्थिक अवसर प्रदान करने और प्रभावी नीतियों को लागू करके हम आधी आबादी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज:

धार्मिक स्थलों पर पुलिस जवान अर्लट मोड पर रहे भ्रमणशील

मऊ। छह दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को मऊ जिले में पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट रही। ड्रोन कैमरों का उपयोग कर नगर में सुरक्षा की निगरानी की गई तो वहीं एसपी खुद क्षेत्रों में भम्रण कर पुलिस व्यवस्था की मॉनीटरिंग करते दिखे। इस दौरान जिले के 12 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर जुमा के समय पुलिस जवानों की तैनाती रही।

एसपी इलामारन जी ने बताया कि छह दिसंबर यानी शुक्रवार को जिले भर में पुलिस की चौतरफा घेराबंदी रही। इसको लेकर जनपद को नौ जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया था। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी के साथ जुमे की नमाज के मद्देनजर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी गई। बताया जाता है कि इस दौरान जिले में पुलिस की कई टीमें सादे कपड़ों में तैनात रही। बताया कि शुक्रवार को छह दिसंबर, जुमे की नमाज और डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस और संभल की घटना को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई।

एसपी ने कहा कि इसको देखते ही बारह थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर पुलिस जवान अर्लट मोड पर रहकर भ्रमणशील रहे। इस दौरान वह नगर के कई धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। इसके अलावा नगर सहित जिले के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रही।

घूँघट की बगावत

8 दिसंबर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

हमारी वसुधैव कुटुंबकम् वाली मान्यता को मिलती चुनौतियां

संभल की जामा मस्जिद का विवाद अभी सुलग ही रहा था कि अजमेर की दरगाह को भी विवाद के घेरे में उलझा दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह दरगाह भी किसी हिंदू मंदिर को ढहा कर बनायी गयी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में कई मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनायी गयीं। वह हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह काम न होता तो अच्छा था। मंदिर अपनी जगह बने रहते, मस्जिदें अपनी जगह बनतीं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विजेता पक्ष अपनी महत्ता और ताकत को साबित करने के लिए इस तरह के दंभपूर्ण काम करता है। अपने ही देश में एक धर्म के मंदिर ढहा कर दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाये जाने के ढेरों उदाहरण हैं। न जाने कितने बौद्ध मंदिर हिंदू मंदिरों को ढहा कर बने थे, और इसका विपरीत काम भी हुआ था। निःसंदेह, धर्म के नाम पर यह लड़ाई निंदनीय ही कही जा सकती है। यह भी समझना होगा कि इस तरह की लड़ाई अनंतकाल तक नहीं चल सकती। कहीं तो इस पर पूर्ण-विराम लगना ही चाहिए था। स्वतंत्र भारत के नेतृत्व में आजादी पाने के दिन अर्थात् 15 अगस्त, 1947 यह पूर्ण-विराम घोषित कर दिया। हमारी संसद ने वर्ष 1991 में एक कानून बनाकर यह तय कर दिया कि देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में रहेंगे जो सन् 15 अगस्त, 1947 को थाझ सिर्फ बाबरी मस्जिद के प्रकरण को इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि यह विवाद तब न्यायालय में पहुंच चुका था। बहरहाल, अब वह विवाद नहीं रहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। उम्मीद की गयी थी कि इसके साथ ही इतिहास को ठीक करने का तर्क भी समाप्त हो जायेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने तो स्पष्ट कहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की कवायद बंद होनी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। कहना चाहिए ऐसा होने नहीं दिया जा रहा। कुछ तत्वों से जुड़े लोग चाहते हैं, कि इस विवाद की आंच जलती रहे। संभल और अजमेर में यही आंच जलाये रखने की कोशिश हो रही है। इससे, किसे क्या लाभ होगा यह वही जाने, पर नुकसान सारे देश को हो रहा है। अतीत के अपराधों को ठीक करने के नाम पर हम अपने भविष्य के प्रति अपराध किये जा रहे हैं!

संविधान की मूलभूत भावना की रक्षा के लिए हमने पूजास्थल कानून बनाया था। तय किया था कि अब किसी पूजा स्थल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट है, यह बीती को बिसार के आगे की सुधि लेने वाला निर्णय था। ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, बेहतर हो। अब इस महत्वपूर्ण निर्णय को स्वयं न्याय व्यवस्था नकारती-सी दिख रही हैं। पहले वाराणसी में, और अब संभल में मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों की न्यायिक जांच करने का आदेश देकर जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल दिया है।

इस संदर्भ में भीड़-तंत्र सांप्रदायिकता को ही हवा दे रहा है। इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है वोट जिहाद जैसे नारों का? यही नहीं, बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे वोट भले ही दिलवा दें, पर इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर आंच ही आयेगी। आज आवश्यकता सांप्रदायिकता की आग पर पानी-मिट्टी डालने की है, लेकिन एक तरह से विवाद को भड़काया ही जा रहा है। ह्यमेरा मंदिर, तेरी मस्जिदह्ल वाला यह खेल अब बंद होना ही चाहिए। विभाजन के बाद जो अल्पसंख्यक अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान नहीं गये थे, उनकी देशभक्ति पर उंगली उठाना सही नहीं है। अब भी कभी-कभी हमारे कुछ नेता देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देकर शायद उन्हें यह जताना चाहते हैं कि वे भारत में अवश्य हैं, पर भारत के नहीं हैं। इस तरह की भावना भड़काने वाले गलत ही कर रहे हैं। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक रिपोर्ट पेश करते हुए एक चेतावनी दी थी देश के बहुसंख्यकों को। उन्होंने कहा था यह हम बहुसंख्यकों को समझना है कि अल्पसंख्यक समुदाय क्या अनुभव कर रहा होगा और यह भी कि हमारे बारे में भी वही सोचा जाये जैसा अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा जा रहा है तो हमें कैसा लगेगा? यह प्रश्न नहीं था, चेतावनी थी जो सरदार पटेल ने देश के बहुसंख्यकों को दी थी। और यह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 1949 में थी, जब लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश को सांप्रदायिकता के खतरे से आगाह किया था। आजादी के इन 75 सालों में ऐसे बहुत मौके आये हैं जब हमने ईश्वर एक है की अपनी मान्यता को विश्व के समक्ष एक आदर्श के रूप में रखा है। यदि हम इस बात को

न्यायिक व्यवस्था से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के पालन का वातावरण बनाने में योगदान दें, न कि विवादों को हवा देने का काम करें।

मानते हैं तो फिर ऐसा कुछ बचा नहीं रहता जो धर्म के आधार पर हमें बांटे। आज संभल या अजमेर जैसे मुद्दे उठाकर हमारी वसुधैव कुटुंबकम् वाली मान्यता को चुनौती दी जा रही है।

सारे विश्व को एक परिवार मानने वाला हमारा दर्शन किसी को पराया नहीं, अपना मानने का ही मंत्र देता है। विवेक का तकाजा है कि हम हिंदू-मुसलमान, सिख या ईसाई में मनुष्य को बांटने की प्रवृत्ति को पूरी ताकत से नकारें। जुड़ना सिर्फ हिंदुओं को नहीं है, देश के हर नागरिक को जुड़ना हैझ्र एक भारतीय नागरिक के रूप में जुड़ना है। संभल में जो हो रहा है अथवा अजमेर में जो किये जाने की कोशिश की जा रही है, वह हमें जोड़ेगी नहीं, सिर्फ तोड़ेगी, बांटेगी।

सर संघचालक मोहन भागवत की इस बात को अमल में लाने की आवश्यकता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की कवायद अब बंद होनी चाहिए। भागवत से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह अपने इस महत्वपूर्ण कथन को अमल में लाने का वातावरण तैयार करें। अपने अनुयायियों को समझाएं कि देश के हर नागरिक का देश पर समान अधिकार है, और यह भी कि हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह देश- हित के बारे में सोचे, देश-हित को सर्वोपरि माने। मंदिर-मस्जिद वाला यह खेल अब बंद होना चाहिए। धार्मिक-स्थलों वाला 1991 वाला कानून देश में ईमानदारी के साथ लागू होना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के पालन का वातावरण बनाने में योगदान दें, न कि विवादों को हवा देने का काम करें। वर्ष 1991 में हमने मंदिर-मस्जिद के नाम पर होने वाले विवादों को समाप्त करने का एक सार्थक प्रयास किया था, उस प्रयास को धार देने की जरूरत है, उसे भुलाकर हम भविष्य के प्रति अपने कर्तव्य को ही भुला रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के साख पर असर

दक्षिण कोरिया ने एक सबक सिखाया है कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत हैं, वहां कैसे लोकतंत्र को पाला-पोसा गया है, उसकी जड़ों को कैसे गहरे स्थापित किया गया है।

दक्षिण कोरिया में घटनाएं अचानक नाटकीय हो गईं. वहां राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मार्शल लॉ की घोषणा - कर दी और उसके कुछ ही घंटे बाद उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि वहां मार्शल लॉ लगाने का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। विपक्षी दल के साथ दक्षिण कोरिया के लोग भी सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों ने साफ तौर पर इस दलील को नकार दिया कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है।

दुनिया में दक्षिण कोरिया को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है. वहां लोकतंत्र में विगत पचास वर्ष में पहली बार ऐसी स्थिति आई है, जब किसी राष्ट्रपति को यह लगा कि देश में मार्शल लॉ लगाना चाहिए. राष्ट्रपति यून ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए जो तर्क दिए, उन पर गौर करना चाहिए. अव्वल तो उन्होंने उत्तर कोरिया का हवाला दिया और इसके अलावा, राज्य विरोधी लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य या सरकार विरोधी या एंटी स्टेट लोगों की वजह से मार्शल लॉ लगाना जरूरी हो गया था। हालांकि, विपक्ष और देश के लोग राष्ट्रपति की इस दलील को पचा नहीं पाए।

वास्तव में, राष्ट्रपति यून के सामने शुरू से ही घरेलू या आंतरिक समस्याएं ज्यादा रही हैं। घरेलू राजनीतिक समस्याओं से आसानी से निजात पाने के लिए ही उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया। उन्हें शायद ऐसे दमदार विरोध की आशंका नहीं थी।

मार्शल लॉ की घोषणा के बाद आपात स्थिति में संसद में प्रस्ताव रखा गया और मार्शल लॉ लगाने के फैसले को नकार दिया गया. कुछ ही देर में मार्शल लॉ को हटाना पड़ा. अब सवाल यह पैदा हो गया है कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा या उन पर महाभियोग चलेगा. इसमें शक नहीं कि दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने राष्ट्रपति के इस फैसले के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाया है. खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति यून की खुद की पार्टी में भी उनका विरोध हुआ. इससे यह भी लगता है कि राष्ट्रपति अपनी पीपुल्स पावर पार्टी को भी साथ लेकर नहीं चल पाए. वह चाहते थे कि जो एंटी स्टेट तत्व देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें खत्म किया जाए और इसके लिए उन्होंने सेना को शक्ति प्रदान कर दी थी। हालांकि, राष्ट्रपति के फैसले के बाद घटनाक्रम में तेजी आ गई और मार्शल लॉ के जमने से पहले ही उसे वापस लेने को मजबूर कर दिया गया। विपक्षी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध का नेतृत्व किया है और अपने सभी सांसदों को तत्काल वोट के लिए संसद बुला लिया। मार्शल लॉ को पलटने के लिए जिस राजनीतिक समर्थन की उम्मीद थी, उसे जुटाने में विपक्ष ने देरी नहीं की। यह भी कहना चाहिए कि मार्शल लॉ को लागू करने के लिए जैसे राजनीतिक समर्थन की जरूरत थी, राष्ट्रपति यून के पास उसका अभाव हो गया और उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा।

मार्शल लॉ का इस्तेमाल आपात स्थिति में दक्षिण कोरिया में पहले भी हुआ है। पिछली बार इसका इस्तेमाल 1979 में हुआ था। 1987 में दक्षिण कोरिया संसदीय लोकतंत्र बना और उसके बाद से कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। अतः वहां की राजनीति में यह एक निर्णायक मुकाम है, जब मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हुई है। मार्शल लॉ का नुकसान यह होता है कि पूरी ताकत फौज को मिल जाती है और नागरिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। राजनीति या मीडिया पर एक तरह से रोक लग जाती है। चूंकि दक्षिण कोरिया की छवि उदारवादी लोकतंत्र की रही है और उसे एक आदर्श देश के रूप में देखा जाता है। आर्थिक रूप से भी वह बहुत मजबूत है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए वहां मार्शल लॉ लगाने की कोशिश ने दुनिया को चकित कर दिया।

अगर इसका असली कारण हम खोजेंगे, तो 2022 में यून सुक येओल राष्ट्रपति चुने गए थे और उसके कुछ ही समय बाद विपक्षी पार्टी ने चुनाव जीतकर संसद में खुद को मजबूत कर लिया। इससे राष्ट्रपति यून को परेशानी होने लगी थी, विपक्ष उनके प्रयासों को रोक दे रहा था। इसके साथ ही, यून के लिए आम लोगों का समर्थन भी बहुत नीचे खिसक गया। यून की पत्नी ने भी बहुत महंगे उपहार स्वीकार किए, इससे भी यून की लोकप्रियता घटी और विवाद बढ़ गए। उपहार को भ्रष्टाचार से जोड़ा गया और यून को राष्ट्रीय टेलीविजन पर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि, उन्होंने इसकी जांच कराने से मना कर दिया. देश में ऐसी अनेक समस्याएं पैदा हुईं, जिन्हें यून संभाल नहीं पाए और उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर लिया। अब स्थितियां उनके बिल्कुल विपरीत चली गई हैं, उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। यून के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन उज्ज्वल छवि वाले दक्षिण कोरिया के लिए यह उससे भी बड़ा झटका है. दक्षिण कोरिया को बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता है, वहां के नेताओं की अपनी विशेष छवि रही है, उन्हें दुनिया में सम्मान मिलता रहा है। ताजा घटनाक्रम से निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया की साख पर तात्कालिक असर हो सकता है। यून ने राजनीति का जो रास्ता दिखाया है, उसे लेकर चिंता बढ़ गई है। क्या किसी नेता को घरेलू स्तर पर राजनीतिक समस्याएं घेर लें, तो वह देश में मार्शल लॉ लगाकर सबको संकट में डाल सकता है? ऐसी उम्मीद कम से कम किसी दक्षिण कोरियाई नेता से अभी तक नहीं थी।

दक्षिण कोरिया ने एक सबक सिखाया है कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत हैं, वहां कैसे लोकतंत्र को पाला-पोसा गया है, उसकी जड़ों को कैसे गहरे स्थापित किया गया है। लोकतांत्रिक देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, उनका मजबूत जमीन पर खड़ा होना जरूरी है। अगर संस्थाएं मजबूत न हों, तो कोई भी नेता व्यक्तिगत परेशानी की वजह से संस्थाओं को संकट में डाल सकता है। दक्षिण कोरिया ने एक सबक सिखाया है कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत हैं, वहां कैसे लोकतंत्र को पाला-पोसा गया है, उसकी जड़ों को कैसे गहरे स्थापित किया गया है। दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र मजबूत है, तभी अपने एक नेता के गलत फैसले से देश अपने को बचा पाया। विपक्ष ने तेजी दिखाई व लोग भी मुखर हुए और यह साबित हो गया कि देश में अगर लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो, तो फिर चंद लोगों के बुरा चाहने से कुछ नहीं बिगड़ता. लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा। यह भी साबित हुआ कि लोग अगर सजग रहें, तो लोकतंत्र में आ रही गिरावट को भी रोका जा सकता है।

आपसी तालमेल के अभाव से लड़ती आप और कांग्रेस

कांग्रेस को जीवनदान देने से आप कर रही परहेज

संसद से लेकर सड़क तक भाजपा या भाजपा-नीत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस और आप कदमताल करती हुई दिखाई तो पड़ती हैं, लेकिन चुनाव आते ही दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। आप के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ भिड़ने में एकता के मोर्चे पर दोनों के साथ आने से जनता में माहौल बन तो जाता है, लेकिन चुनावी तालमेल करने से आप को कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। इस बार भी आप को डर है कि कांग्रेस का आधार वोट आप को ट्रांसफर होने की बजाय कहीं भाजपा को फायदा न पहुंचा दे। वैसे भी पिछले चुनाव के आंकड़े यही बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2024 के लोक सभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा सभी सात सीटें जीत गई। आप भी खाली हाथ रही। 2019 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस को 23 फीसद वोट मिलने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी। 2014 के लोक सभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 15 फीसद वोट पाने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

अलबत्ता,2009 में कांग्रेस दिल्ली की सातों लोक सभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, साथ ही वोटों की 57 फीसद हिस्सेदारी भी उसने हासिल की थी। इस तरह कांग्रेस के वोटों का यह छीजन आप को डूबती नैया पर सवार होने जैसा लग रहा है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सफाये के बाद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए आप और कांग्रेस ने मिल कर सरकार बनाई थी। परंतु यह सरकार 49 दिनों तक ही चल सकी। बाद में वर्ष 2015 में आप खुद की बदौलत सत्ता में आई और कांग्रेस वर्ष 2015 और 2020, दोनों विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब तो आप को दिल्ली में कांग्रेस टक्कर में ही नहीं दिखती। साफ है कि आप अपना मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ मान रही है और अपनी बदौलत कांग्रेस को जीवन दान देने से परहेज कर रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दस्तक देते ही विपक्षी एकता एक बार फिर से कटी पतंग जैसी हो गई है, जो कभी इस दीवार और कभी उस स्तंभ से टकरा कर लुटी-पिटी सी नए तारणहार की राह जोह रही है। आम आदमी पार्टी (आप) के अगुवा अरविंद केजरीवाल ने साफतौर पर घोषित कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी वर्ष में संपन्न होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सभी 70 सीटों पर खुद उम्मीदवार उतारेगी। मजबूरी में कांग्रेस नेताओं को भी सभी सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा करनी पड़ी है।

दूसरे दल भी कांग्रेस का साथ देने को घाटे का सौदा मान रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा गठबंधन इंडी अलायंस के रूप में बना जरूर है लेकिन यह प्रभाव छोड़ता नहीं दिखलाईपड़.रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ने पहली बार कांग्रेस को ठेंगा दिखाया है बल्कि इससे पहले भी पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किए बिना चुनाव जीत कर और वहां यह सरकार बना कर दिखा चुकी है।

इस मामले में कांग्रेस भी दूध की धोई नहीं है, बल्कि लोक सभा चुनाव के तुरंत बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुद को सरकार में आना तय मान कर कांग्रेस के नेता आप से गठबंधन के विरोध में लगातार बयान देते रहे। आखिरकार, दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो सका और दोनों ही पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकीं। इस तरह की स्थिति पहले गुजरात समेत दूसरे कई राज्यों के चुनावों में भी रही है। दोनों पार्टियों को सीटों का तालमेल नहीं होने का खमियाजा उठाना पड़ता रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और आप दोनों के अपने-अपने पूर्वाग्रह हैं। आप मान कर चलती है कि कांग्रेस का देश में कहीं कोई जनाधार नहीं है या तो वह क्षेत्रीय दलों की बैसाखी पर चल रही है या फिर उसे नाराज वोटों का फायदा मिल जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव लगभग 10 महीने बाद हैं। लेकिन अभी से ही कांग्रेस के नेता अपने आला कमान की जगह राजद सुप्रीमो की चौखट पर ज्यादा माथा टेक रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की वैतरणी लालू-तेजस्वी के बिना पार नहीं हो सकते। कांग्रेस की ओर से पूर्णिया लोक सभा सीट से पप्पू यादव को उतारने की पूरी तैयारी के बावजूद राजद की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं दे सकी। आखिरकार, पप्पू जीते लेकिन निर्दलीय सांसद के तौर पर। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में तो लालू प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में साफ तौर पर कहा कि उन्हें राज्य सभा सदस्य कांग्रेस ने नहीं, बल्कि राजद ने बनाया है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से भी बार-बार गठबंधन तोड़ देने की चेतावनी दी जाती रहती है। कुछ और भी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने जूनियर पार्टनर के तौर पर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर, इन हालात में कांग्रेस जाए तो जाए कहां? लंबे समय तक देश पर राज करने और अधिकतर राज्यों में सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस की यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है। कांग्रेस के वोट बैंक के तीन मुख्य आधार-दलित, मुस्लिम और सवर्ण-उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं।

ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों की बदौलत अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में नीतिगत विकल्प देकर व्यापक पहलकदमी करना और संघर्ष के रास्ते नई पहचान बना कर नये सिरे से जनाधार तैयार करने का रास्ता ही कांग्रेस के पास बच रहता है।

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई : डॉ. रमेश ठाकुर

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें जमीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवजा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबल हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंड़ियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे।

प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हांलाकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस और

दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाईं। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, ह्यआग में घी डालनेह्ल का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com